प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

04.04.2024 / प्रादेशिक समाचार / 09:20 बजे

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने नव अधिनियमित आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सहित अन्य सभी संबंधित विभागों से उचित प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा है। ये कानून पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। इस संबंध में कल शिमला में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस, न्याय अधिकारियों, राज्य फॉरेंसिक विज्ञान, जेल अधिकारियों और फील्ड स्टॉफ को नए कानूनों के संबंध में डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजिटाईजेशन को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों में आधुनिक तकनीक को समाहित किया गया है।

मिड–डे मील

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मिड–डे मील के तहत हिमाचल को 25 करोड़ 95 लाख रूपए की चौथी किस्त जारी कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से पीएबी की बैठक में यह जानकारी दी गई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि पीएम पोषण योजना के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए वित्त वर्ष के लिए भी 103 करोड़ रूपए की राशि को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सख्त गाइडलाईन जारी की है जिसके अनुसार अब स्कूलों में दोपहर के खाने की समय–समय पर स्वच्छता जांच भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पीएम पोषण योजना में हिमाचल के साढ़े पांच लाख बच्चे शामिल हैं।

प्रवेश परीक्षा

जेईई मेन 2024 के दूसरे चरण के लिए प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इस परीक्षा के लिए 12 लाख 57 हजार विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। एनटीए द्वारा 297 शहरों के 5 सौ 44 परीक्षा केन्द्रों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है।

जागरूकता कार्यक्रम

कुल्लू के उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष तोरूल एस रवीश ने कहा है कि जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में आज आपदा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को आज ही के दिन 1905 को प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप आया था।

उन्होंने कहा कि इस दिन को आपदा जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सके। इस अवसर पर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में मॉकड्रिल, भाषण व निबंध लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

कार्यशाला

लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कल जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। किन्नौर के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में मतदान कर्मियों की अहम भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट सहित मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने संबंधी जानकारी अधिकारियों को दी गई।

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर....

आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग–अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है लोकतंत्र सेनानियों की रोकी गई सम्मान राशि जारी करे प्रदेश सरकार। दैनिक जागरण के शब्द हैं हाईकोर्ट ने राशि रोकने के प्रदेश सरकार के निर्णय को ठहराया गलत। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश संघ की याचिका स्वीकार करते हुए जारी किए आदेश।

हिमाचल दस्तक की एक खबर है फिलहाल कांग्रेस का कोई भी टिकट फाइनल नहीं–6 अप्रैल को होगी स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक।

कैंसर के इलाज में सहायक औषधीय प्रजाति बिरमी खतरे में शीर्षक से अमर उजाला लिखता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में किया शामिल।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल में मोदी सरकार ने 10 वर्षों में सुदृढ़ की रोड कनैक्टिविटी।

पंजाब केसरी की एक खबर है हिमाचल के कर्मचारी–पैंशनरों को मिलेगा चार फीसदी डीए–केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से राज्य सरकार को मिला ग्रीन सिग्नल।

हिमाचल दस्तक राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के हवाले से लिखता है निर्दलीय विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष ही लेंगे फैसला–राजभवन अपनी मर्यादा में रहकर ही कर रहा काम।

रेगुलाइजेशन पर सरकार लेगी एकल मंजूरी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किया साफ, चुनाव आयोग को विभागों के अलग–अलग केस नहीं भेजेंगे।